eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका एवं संभावनाएं

डा0 मनोज कुमार अवस्थी[1]
[1]सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर, चित्रकूट, उ0प्र0

Received: 01 April 2025 Accepted & Reviewed: 05 April 2025, Published: 30 April 2025

Abstract

यह शोधपत्र भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप, उसकी भूमिका, प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा है। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, कैशलेस ट्रांजैक्शन, फिनटेक, स्टार्टअप्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे घटकों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भारतीय सामाजिक–आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। यह अध्ययन डिजिटल क्रांति के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए यह बताने का प्रयास करता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने की दिशा में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्य शब्द– डिजिटल अर्थव्यवस्था, भारत, ई–गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, फिनटेक, कैशलेस लेन–देन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, आत्मनिर्भर भारत

Introduction

21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीकों ने सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए डिजिटल परिवर्तन महज तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि समावेशी विकास का एक माध्यम बन चुका है। डिजिटल अर्थव्यवस्था न केवल उत्पादकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि सेवाओं की पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन को भी सुगम बनाती है। भारत ने पिछले एक दशक में सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल संचार, इंटरनेट सेवाओं, ई–गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से 2015 में प्रारंभ हुआ शडिजिटल इंडियाश कार्यक्रम इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। डिजिटल भुगतान प्रणाली (जैसे UPI, BHIM), ई–मार्केटप्लेस, स्टार्टअप और नवाचार आधारित उद्यम, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की स्थापना ने भारत को एक डिजिटल समाज की ओर तेजी से अग्रसर किया है। हालाँकि, इस परिवर्तन के साथ कई सामाजिक, तकनीकी, विधायी और सुरक्षा संबंधित चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, तकनीकी कौशल का अभाव तथा डिजिटल सेवाओं की क्षेत्रीय असमानता जैसे विषय इस शोध का प्रमुख केंद्रबिंदु हैं। यह शोध पत्र भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास, उसकी वर्तमान स्थिति, प्रभाव, चुनौतियाँ और संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों, शोधार्थियों और डिजिटल उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य भी करता है।

परिकल्पना– यह परिकल्पना की गई है कि भारत में डिजिटल तकनीकों का तीव्र प्रसार न केवल आर्थिक विकास को गति देता है, बल्कि सामाजिक समावेशन, पारदर्शिता और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

निभाता है। यदि नीति–निर्माण, डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता को समान रूप से प्राथमिकता दी जाए, तो भारत वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है।

शोध प्राविधि– यह अध्ययन एक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है। शोध के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोत– सरकारी रिपोर्टें, नीतिगत दस्तावेज, नीति आयोग की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट भाषण, आदि।

द्वितीयक स्रोत– शोध लेख, पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स और डिजिटल इंडिया मिशन से संबंधित आँकड़े।

डेटा संग्रह– भारत सरकार की वेबसाइटों, RBI, NPCI, NITI Aayog, और MeitY के पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

प्रविधि– तुलनात्मक विश्लेषण, समय–श्रृंखला विश्लेषण, और नीति मूल्यांकन की विधियों का प्रयोग किया गया है।

यह शोध मुख्यतः 2015– 2024 की अवधि को ध्यान में रखते हुए भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास, उपलब्धियों और संभावनाओं का अध्ययन करता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जो मुख्यतः डिजिटल तकनीकों जैसे इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से संचालित होती हैं। इसमें ई–कॉमर्स, ऑनलाइन सेवाएँ, डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और डिजिटल अवसंरचना शामिल होती है। वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान वैश्विक जीडीपी में निरंतर बढ़ रहा है। विश्व बैंक, OECD और IMF जैसी संस्थाओं ने डिजिटल तकनीक को आर्थिक समृद्धि, समावेशन और नवाचार का प्रमुख स्तंभ माना है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी हैं। Amazon, Google, Alibaba, और Tencent जैसी कंपनियाँ डिजिटल व्यापार का वैश्विक चेहरा बन चुकी हैं।

डिजिटल व्यापार, क्रिप्टोकरेंसी, ई–सेवाएँ और वर्चुअल कार्य संस्कृति अब वैश्विक प्रवृत्ति बन चुकी हैं। भारत में डिजिटल परिवर्तन की यात्रा 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के साथ आरंभ हुई, जब सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। वर्ष 2000 के बाद मोबाइल क्रांति और इंटरनेट की पहुँच में वृद्धि ने डिजिटल बदलाव की नींव रखी। 2005 नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान लागू किया गया। 2009 UIDAI की स्थापना और आधार योजना की शुरुआत हुई। 2010– 2014 डिजिटल सेवाओं में पायलट प्रयोग बढा (जैसे – DBT, ई–सेवा केंद्र)। 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2016 विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान में तेजी आई। 2020– 2023 कोविड–19 महामारी के दौरान ई–शिक्षा, टेलीमेडिसिन, रिमोट वर्क को अभूतपूर्व बल मिला। इस ऐतिहासिक विकास ने भारत को एक डिजिटल रूपांतरित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया है। इस प्रकार डिजिटल इंडिया, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढाँचा का विकास,

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

डिजिटल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, व भारत नेट परियोजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवा पहुँचाना। UMANG, DigiLocker, e Hospital, GeM जैसे प्लेटफार्मों का निर्माण। आधार आधारित प्रमाणीकरण और मोबाइल, जन, आधार का एकीकरण मुख्य रणनीतियाँ रहीं। लगभग 90 करोड़ से अधिक आधार लिंक बैंक खाते, UPI लेनदेन में विश्वस्तरीय वृद्धि, लगभग 5 लाख CSCs (Common Service Centres) का संचालन, डिजिटल भुगतान में ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी उपलब्धियाँ रहीं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने शासन, सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है और भारत को डिजिटल महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई, भीम, रूपे कार्ड, और फिनटेक क्रांति ने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास वित्तीय समावेशन और नकदी रहित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल भुगतान के साधनों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिलकर डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने हेतु कई पहलें शुरू कीं। UPI को 2016 में NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक रियल–टाइम पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से बैंक–टू–बैंक फंड ट्रांसफर को संभव बनाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं– 24•7 सेवा उपलब्धता, एक ही मोबाइल ऐप से कई बैंक खातों को लिंक करने की सुविधा, क्यूआर कोड आधारित भुगतान, सुरक्षित एवं सरल इंटरफेस व 2023 तक UPI का मासिक लेन–देन मूल्य 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुँच गया है।

भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) ऐप को दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। यह UPI आधारित ऐप है, जिसे विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठभ्प्ड ऐप ने डिजिटल भुगतान की पहुँच को आम जनता तक सरल और सुलभ बनाया।

रूपे, NPCI द्वारा विकसित एक घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है। इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को एक सस्ता और सुरक्षित कार्ड भुगतान माध्यम प्रदान करना है। रूपे कार्ड डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के रूप में उपलब्ध हैं। यह कार्ड जनधन योजना के तहत लाखों लोगों तक पहुँचाया गया, जिससे वित्तीय समावेशन को बल मिला।

फिनटेक शब्द 'फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी' का संक्षिप्त रूप है। भारत में फिनटेक स्टार्टअप्स की संख्या 2023 तक 10,000 से अधिक हो चुकी है। ये स्टार्टअप्स बैंकिंग, बीमा, ऋण, निवेश, और वॉलेट सेवाओं में नवाचार कर रहे हैं। Paytm, PhonePe, Razorpay, Zerodha जैसे स्टार्टअप्स ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं को आम आदमी के लिए सुविधाजनक बना दिया है। इससे नकदी पर निर्भरता में कमी, लेन–देन की पारदर्शिता, टैक्स संग्रह में वृद्धि, ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुँच का विस्तार प्रमुख प्रभाव हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली और फिनटेक नवाचार ने भारत को विश्व के अग्रणी डिजिटल भुगतान बाजारों में शामिल कर दिया है और यह आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अनेक परस्पर जुड़े घटकों पर आधारित है जो सामूहिक रूप से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन को गति देते हैं। इन घटकों में निम्नलिखित प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं। ई–गवर्नेंस का तात्पर्य प्रशासनिक

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने से है, जिससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गति सुनिश्चित होती है। माईगॉव पोर्टल, डिजी लॉकर, ई–हॉस्पिटल, उमंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को सेवाएं सुलभ कराते हैं। भारत में ई–कॉमर्स उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म ने उपभोक्ताओं की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। MSME सेक्टर को भी इसने एक नया बाज़ार प्रदान किया है। फिनटेक का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण है। भारत में पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, और यूपीआई जैसी सेवाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से फैल रही हैं। इससे बैंकिंग सेवाएं उन तक पहुंची हैं जो पहले बैंकिंग प्रणाली से वंचित थे।

राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म (DIKSHA) SWAYAM और NPTEL जैसे पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला है। कोरोना महामारी के दौरान इस घटक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। ई–संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाएं विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए क्रांतिकारी साबित हो रही हैं। ई–नाम, कृषि एप्स, और डिजिटल मंडियां किसानों को कृषि उत्पादों की उचित कीमत दिलाने, मौसम जानकारी और फसल बीमा सेवाएं प्राप्त करने में मदद कर रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत डेटा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा है। भारत में डिजिटल लॉकर, आधार डाटा सेंटर, सीईआरटी–इन जैसी संस्थाएं डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ए आई और ब्लॉकचेन तकनीकों का उपयोग स्वास्थ्य, वित्त, परिवहन और प्रशासनिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन आधारित भू–अभिलेख प्रणाली, हेल्थ रिकॉर्ड और सप्लाई चेन प्रबंधन में पारदर्शिता ला रही है। इन सभी घटकों की परस्पर क्रिया भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक समग्र और प्रभावशाली दिशा प्रदान करती है। इसके माध्यम से न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ रही है बल्कि आर्थिक समावेशन और नवाचार को भी बल मिल रहा है।

तालिका 01

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान (2014–2024)

वर्ष	डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान (USD अरब में)	कुल GDP में प्रतिशत योगदान (%)
2014	200	7.5 प्रतिशत :
2016	270	9.3 प्रतिशत
2018	355	11.0 प्रतिशत
2020	435	13.0 प्रतिशत
2022	550	15.5 प्रतिशत
2024′	720 (अनुमानित)	18.0 प्रतिशत (अनुमानित)

स्रोत– MeitY (Ministry of Electronics and Information Technology), NASSCOM, RBI Reports, 2023

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था दोनों के ही स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। इसका प्रभाव सामाजिक समावेशन, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और वित्तीय भागीदारी जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से समाज के उन वर्गों तक भी सरकारी योजनाएं और सेवाएं पहुंच सकी हैं जो पहले हाशिए पर थे।

ई–गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सब्सिडी और सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई–कॉमर्स, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल शिक्षा ने महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि उन्हें घरेलू स्तर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने का अवसर भी दिया है। डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने से आईटी, बीपीओ, ई–कॉमर्स, डेटा एनालिटिक्स, और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। ग्रामीण युवाओं को डिजिटली प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूर–दराज़ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसी तरह, टेलीमेडिसिन और हेल्थ एप्स के माध्यम से सस्ती और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं।

तालिका 02

डिजिटल भुगतान (Digital Payments) में वृद्धि (UPI आधारित लेन–देन)

वर्ष	कुल UPI लेन–देन (संख्या में, अरब में)	कुल राशि (₹ लाख करोड़ में)
2017	0.09	0.15
2019	1.35	21.3
2021	3.9	73.0
2023	8.0	139.0
2024’	10.5 (अनुमानित)	170.0 (अनुमानित)

स्रोत– NPCI (National Payments Corporation of India) RBI Bulletin 2024

डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाएं आज गांव–गांव तक पहुंच चुकी हैं। जन–धन योजना, मोबाइल बैंकिंग, और यूपीआई जैसी सेवाएं वित्तीय समावेशन को गति दे रही हैं। इससे लोगों की बचत और निवेश की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। डिजिटल माध्यमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं की पहुंच संभव हो पाई है जिससे विकास संतुलित हो रहा है।

डिजिटल प्रणाली ने मध्यस्थों की भूमिका को कम किया है जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। सरकारी सेवाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है और समान अवसर प्रदान किए हैं। यह एक समावेशी, न्यायसंगत और स्थायी विकास की ओर भारत को अग्रसर कर रही है।

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

तालिका 03

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रमुख पहलें और लाभार्थी (2015–2024)

पहल का नाम	शुरुआत वर्ष	लाभार्थी (करोड़ में)	मुख्य उद्देश्य
डिजिटल इंडिया मिशन	2015	135	डिजिटल साक्षरता, सेवाओं की पहुंच
पीएमजीदिशा	2017	6.2	डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण
उमंग ऐप	2017	10.5	सरकारी सेवाएं मोबाइल पर
डिजीलॉकर	2015	20.4	दस्तावेज़ों का ऑनलाइन भंडारण
भारत नेट परियोजना	2016	3.1 लाख ग्राम पंचायतें	ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

स्रोत– Ministry of Electronics – IT Digital India Dashboard 2024

डिजिटल भुगतान प्रणाली भारत में वित्तीय समावेशन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। विशेष रूप से 2016 के विमुद्रीकरण के पश्चात डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पहलों ने डिजिटल भुगतान को तेज़, सुरक्षित और किफायती बनाया है। UPI ने भारत में भुगतान की प्रणाली को सरल, त्वरित और सुलभ बनाया है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिससे एक ही ऐप से कई बैंक खातों का संचालन किया जा सकता है। NPCI द्वारा संचालित यह प्रणाली आज लाखों लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप ने विशेषकर ग्रामीण और अल्पशिक्षित जनता को डिजिटल भुगतान की ओर प्रेरित किया है। इसकी सरलता और हिंदी सहित कई भाषाओं में उपलब्धता इसकी सफलता का आधार है। पेटीएम, फोनपे, गूगल पे जैसे ऐप्स के माध्यम से मोबाइल वॉलेट और क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान का चलन बढ़ा है। छोटे दुकानदारों, ठेले वालों, और कारीगरों के लिए यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से बिना कार्ड और मोबाइल के भी भुगतान और नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा की पहुंच संभव हो पाई है। जन–धन योजना, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाओं के माध्यम से लाखों नागरिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं। इससे न केवल बचत और निवेश की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, बल्कि सब्सिडी एवं सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हालांकि भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसके सामने कई गंभीर चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या अभी भी डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ है। डिजिटल साक्षरता की कमी डिजिटल सेवाओं के व्यापक उपयोग में बाधा बनती है। भारत के कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जिससे डिजिटल सेवाओं की पहुँच सीमित रह जाती है। डिजिटल लेन–देन में डेटा चोरी, हैकिंग और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए पर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना की आवश्यकता है। अधिकांश डिजिटल प्लेटफॉर्म अंग्रेजी में हैं, जिससे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को कठिनाई होती है। इसके अलावा

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

तकनीकी जटिलताएं भी उपयोग में बाधा डालती हैं। देश के कुछ हिस्सों में बैंकिंग कोर प्रणाली, डिजिटल सर्वर, बिजली और तकनीकी उपकरणों की कमी से डिजिटल सेवाओं का विस्तार बाधित होता है।

तालिका 04

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या (2015–2024)

वर्ष	इंटरनेट उपयोगकर्ता (करोड़ में)	शहरी क्षेत्र (प्रतिशत)	ग्रामीण क्षेत्र (प्रतिशत)
2015	30.2	65	35
2018	48.1	60	40
2021	76.3	55	45
2023	88.7	50	50
2024′	95.0 (अनुमानित)	48	52

स्रोत– Internet and Mobile Association of India (IAMAI), TRAI Annual Report 2024

डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत की संभावनाएं अत्यंत व्यापक हैं। यदि मौजूदा बाधाओं को रणनीतिक ढंग से हल किया जाए, तो भारत विश्व की अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में स्थान पा सकता है। ए आई आधारित सेवाएं जैसे चौटबॉट, वॉयस असिस्टेंट, और डेटा एनालिटिक्स भारत के सेवा क्षेत्र को अधिक दक्ष बना सकती हैं। भविष्य में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग भूमि रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, और सप्लाई चेन प्रबंधन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देकर भारत एक स्थायी डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर हो सकता है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार की योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन हब्स आदि नवाचार को प्रोत्साहित कर रही हैं। भारत अपनी डिजिटल सेवाओं जैसे आईटी आउटसोर्सिंग, क्लाउड सेवाएं, और सॉफ्टवेयर निर्यात के माध्यम से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

तालिका 05

डिजिटल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं (2020–2024)

क्षेत्र	2020 में रोजगार (लाख में)	2025 अनुमानित (लाख में)	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
IT@ITES	43	70	10.2 प्रतिशत
ई–कॉमर्स	15	28	12.5 प्रतिशत
डिजिटल मार्केटिंग	5.8	14.3	19.8 प्रतिशत
साइबर सुरक्षा	2.5	7.6	22.5 प्रतिशत
फिनटेक	1.2	3.8	24.3 प्रतिशत

स्रोत– NASSCOM Future Skills Report 2023, Ministry of Skill Development

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

eISSN 3049-2610
RESEARCH STREAM
A Bi-Annual, Open Access Pear Reviewed International Journal
Volume 02, Issue 01, April 2025

निष्कर्ष– भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है। यह न केवल आर्थिक गतिविधियों को आधुनिक बना रही है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया, UPI, फिनटेक सेवाएं, ई–गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पुनर्परिभाषित किया है। हालांकि, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, अवसंरचना और तकनीकी सुलभता से जुड़ी समस्याएं इस प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। यदि नीति–निर्माता इन चुनौतियों का समाधान समुचित रूप से करें तो डिजिटल भारत एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन सकता है।

अनुशंसाएं–

- डिजिटल साक्षरता अभियान का विस्तार– ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के लिए केंद्रित कार्यक्रम संचालित किए जाएं।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार– भारतनेट जैसी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त रूप में क्रियान्वित किया जाए।
- साइबर सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना– डेटा सुरक्षा के लिए सख्त कानून और जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।
- स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं– सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुभाषी बनाया जाए जिससे हर वर्ग को लाभ मिल सके।
- नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन– फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।
- डिजिटल गवर्नेंस में पारदर्शिता– ई–गवर्नेंस सिस्टम को नागरिक–केंद्रित बनाते हुए सभी सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी की जाएं।
- डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहन– छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाए।
- ब्लॉकचेन और ए आई तकनीकों का विस्तार– इन तकनीकों को भूमि रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड और सरकारी डेटा में लागू किया जाए।
- प्राइवेट–पब्लिक भागीदारी– डिजिटल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- मूलभूत अवसंरचना विकास– बिजली, नेटवर्क और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

सन्दर्भ सूची–

1- डिजिटल इंडिया एक समग्र अध्ययन, डॉ. संजय कुमार मिश्रा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली वर्ष 2020, ISBN: 9789352669863

2. डिजिटल युग में भारत का परिवर्तन, डॉ. शिवानी वर्मा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वर्ष 2019 ISBN: 9788194050320

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025

3. डिजिटल भारत और ई–गवर्नेंस, डॉ. कमलेश जोशी, राजकमल प्रकाशन, वर्ष 2021 ISBN: 9789385755356

4. भारतीय अर्थव्यवस्था और डिजिटल क्रांति, डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा, भारत बुक सेंटर वर्ष 2018, ISBN: 9788193534075

5. साइबर सुरक्षा और डिजिटल खतरें, डॉ. मुकेश कुमार, अरिहंत पब्लिकेशन, वर्ष 2022, ISBN: 9789389607170

6. **Digital India: Understanding Information, Communication and Social Change,** Pradip Ninan Thomas Publisher: SAGE Publications India, Year: 2017, ISBN: 9789386062958

7. **India Connected: Mapping the Impact of New Media,** Author: Sunetra Sen Narayan & Shalini Narayanan, Publisher: SAGE Publications, Year: 2016, ISBN: 9789386062200

8. **The Rise of the Indian Startup Ecosystem,** Author: TiE Bangalore, Publisher: Penguin Random House Year: 2021, ISBN: 9780670095401

9. **Fintech in India: A Global Perspective,** Author: Amitabh Rajan, Publisher: Rupa Publications Year: 2022 ISBN: 9789355203576

10. **Cyber Security in India: Challenges and the Way Forward,** Author: Harsha Vardhan, Publisher: Pentagon Press , Year: 2020, ISBN: 9789390095332

11. **Digital Economy and Society: India and Global Perspectives,** Author: P.K. Paul et al., Publisher: New India Publishing Agency, Year: 2018, ISBN: 9789386546519

12. **India's Skills Challenge: Reforming Vocational Education and Training to Harness the Demographic Dividend,** Author: Santosh Mehrotra, Publisher: Oxford University Press, Year: 2014, ISBN: 9780199451184

13. **India's Long Road: The Search for Prosperity,** Author: Vijay Joshi, Publisher: Oxford University Press Year: 2017, ISBN: 9780190610139

14. **The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence,** Author: Don Tapscott Publisher: McGraw-Hill, Year: 1996 (Revised Ed. 2014), ISBN: 9780071835558

15. **Reimagining India in the Digital Era,** Author: Nandan Nilekani & Viral Shah, Publisher: Penguin Allen Lane, Year: 2019, ISBN: 9780670092769

© RESEARCH STREAM JOURNAL, 2025